UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

नक्सलवादी समस्या के क्षेत्रीय प्रारूप का विशेष अध्ययन उत्तरप्रदेश से चन्दौली जिले के विशेष संदर्भ में

[1]**Manoj Singh Yadav,** Research Scholar
[2]**Dr. Hemlata Mishra,** Professor
Department Of Political science, Shri Dev Suman University
Rishikesh campus Haridwar

संदर्भ

आज देश के 16 राज्यों में जो 200 जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं। इनमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश। हांलाकि अगर आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से जोड़ा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में पनप रहे नक्सलवाद यानी माओवादी संगठन न के बराबर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश का माओवाद अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। यहां के माओवाद की उत्पत्ति माओवादी संगठनों के जरिये कम, प्रशासन के जरिये ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का कथित नक्सलवाद कैमूर क्षेत्र के तीन जिलों, मिरापुर, चन्दौली और सोनभद्र एवं कुछ हद तक बुन्देलखंड में फैला है। नक्सली संगठनों की सबसे ज्यादा गतिविधियां कैमूर क्षेत्र में हैं चूंकि यह क्षेत्र झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इस क्षेत्र में इन संगठनों की गतिविधियां बिल्कुल नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वैसे कैमूर एक ऐसा क्षेत्र है, जो माओवाद को पनपने के लिये अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। समय रहते आदिवासियों को जनजाति का दर्जा न मिलना, उनकी कामों और जंगल में जबरन बेदखली, फर्जी एनकाउंटर, सामंती अत्याचार व स्थानीय लोगों के अधिकारों के हनन से उद्योगों की स्थापना यहां नक्सलवादियों को जगह मिलने के मूल कारण हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भूमि सुधार कानूनों को सही प्रकार से लागू नहीं करना और राजस्व व वन विभाग द्वारा सांमतों और पूंजीपतियों से मिलकर भूमि के रिकाडरे में भारी हेरा–फेरी।

प्रस्तावना

नक्सलवाद एक विचारात्मक राजनीतिक आर्थिक संघर्ष है। जो शासकों वर्ग को राज सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है, जिसके मालिक देश विदेशी पूंजीपति भूस्वामी ठेकेदार दलाल नौकरशाह आदि हैं, जो बहुसंघीय श्रमजीवी वर्ग पर शासन करते हैं। भारत में नक्सलवाद पनपने के लिए असंतुलन और असमानता काफी हद तक जिम्मेदार है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में भी असंतुलन और असमानता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया, किंतु 70 वर्ष के बाद भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकें। वर्तमान में विकास

को व्यवस्था का अंग मानकर अनदेखी की जा रही है। नक्सलवाद के विस्तार का यह भी एक बड़ा कारण है। नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या हैं और बीते हुए कुछ सालों में इसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में नक्सलियों का प्रभाव पशुपति (नेपाल) से तिरूपति (आंध्रप्रदेश) तक हो चुका है। धन बल में ये काफी मजबूत हैं। नक्सली क्षेत्रों में आंबटित पैसा नेता अफसरों और ठेकेदारों के बीच बंट जाता है। बात यही खत्म नहीं होती और यही पैसा अंतत नक्सलियों तक पहुंच ही जाता है जिसका उपयोग वे हिंसात्मक गतिविधियों में करते हैं।

1967 में ही कानू सनथाल, चारू मजूमदार और जंगल सन्थाल जैसे नेताओं ने भूमिहीनों का नेतृत्व किया और उन्हें जमीन दिलवाने के लिए आन्दोलन खड़ा किया। किन्तु प्रशासन ने सरकार के आदेश के बाद उनके आन्दोलन को ध्वस्त कर दिया इसके बाद इन नेताओं ने सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए सशस्त्र आन्दोलन आरम्म किया और यह आन्दोलन क्षेत्रीय और भौगोलिक समीओं को लाघंकर देश भर में बिखर गया है।

इस आन्दोलन में, गरीब तबका तो सशस्त्र लगा था उसी के साथ सुशिक्षित युवा वर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग ने दो कदम आगे बढकर इस क्रान्ति का आगाज किया क्योंकि आजादी प्राप्ति के बाद सभी ने सुनहरे सपने सजोंये थे। जैसा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति की अर्द्धरात्रि को स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुये भारत के ग्रामीण व अल्पसंख्यक, गरीब किसानो, मजदूरो, विकलागो, बुद्धों, महिलाये व मासूम बच्चो के आखों से ऑसू पोंछने का वादा किया था परन्तु आजाद भारत में देश के कुछ सीमान्तवादियो ने इन गरीब असहाय लोगों को सपने देखने से पहले ही शोषण, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि के माध्यम से इनको अपाहिज बना दिया, जिन्हें जीने के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर वैशाखी रूपी विकास के कार्यक्रमों को संचालित कर इनकी समस्याओं को कम करने का प्रयास किया परन्तु बीच के विचौलियों ने कभी भी इन योजनाओ को पूर्णतः ग्रामीण स्तर तक पहुँचने ही नहीं दिया और ये आजादी से पहले की गुलामी की जंजीरो में पुनः जकडतें चले गये और भारतीय क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछडते गये और समाज के पूंजीपतियो के शिकार होते चले गये अर्थात इनके पैर शोषण के दलदल में फंसते चले गये और अपने जीवन के उन मूलभूत आवश्यकताओं (जैसे रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि) के लिये रहम की भीख मागते रहे लेकिन बुर्जुआ वर्ग ने कभी इन्हे फूटी आखों से भी नहीं देखा ।

गरीब वर्ग, आदिवासी, दलित, इन दोनों से त्रस्त है, खासतौर पर महिलाएं जिनको दोनों ओर के हमले सहने पड़ते हैं क्योंकि कहीं न कहीं राजसत्ता और माओवादियों के बीच उनकी जगह खत्म होती जा रही है। चिन्ता का विषय है कि इस जगह को कम करने में खुद सरकार या यहां की स्थानीय राजनीति ही लगी है ताकि लोग बुनियादी विकास के ढांचे के सवाल को न उठा सकें। वहीं प्रशासन के लिए भी नक्सलवाद का हौवा खड़ा करना जरूरी है ताकि लोगों पर दमन करना आसान हो सके। वे कतई नहीं

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

चाहते कि इन इलाकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़े, क्योंकि नक्सलवाद के नाम पर आने वाला तमाम फंड पूर्ण रुप से बंद हो जाएगा। दूसरी ओर आम लोगों द्वारा इस जगह को बनाने के लिये एक दबाव बन रहा है। एक तो स्थानीय स्तर पर और एक राजनैतिक स्तर पर, यह एक सच्चाई है कि मायावती सरकार के सत्तासीन होते ही माओवादी संगठनों का फैलाव बहुत ही सिकुड़ कर रह जाता है, यह पहले भी हुआ है और यह अब भी हो रहा है। मायावती के ही शासन काल में सन् 2002 में 42 दलित आदिवासियों पर पोटा हटाया गया है और अभी हाल ही में छह अन्य कथित नक्सलवादियों को दोषमुक्त किया गया। स्थानीय स्तर पर इतने अत्याचार और विषमता के बाद भी गरीब तबके माओवादी संगठन में शामिल नहीं हो रहे। माओवादी संगठन भी कामयाब हों ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, वे भी एक भटकाव की स्थिति में हैं और वे कैमूर की पेंचीदा परिस्थितियों के प्रति कोई सकारात्मक पहल भी नहीं कर पाए। हालांकि इसके विपरीत यह तथ्य शायद हर वन क्षेत्र में मौजूद होगा कि आदिवासी एवं अन्य गरीब तबके, खासतौर पर महिलाएं अपनी चेतना के आधार पर जहां राजसत्ता को चुनौती दे रही हैं वहीं माओवादी संगठनों को भी यह संदेश दे रही हैं कि उनके द्वारा दिखाए जाने वाले जन विरोधी हथियार बंद रास्तों पर चल कर अपने छीने गए अधिकारों को पाने की आखिरी मंजिल तक पहुंचना नामुकिन है। लेखिका मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं।

भारत सरकार ने नक्सलवादियों के ऊपर कछ स्थितियों का संग्रह किया है। जिसका जिक्र समय–समय पर जारी सरकार के प्रपत्रों एवं अन्य माध्यमों से मिलता है। इनमें इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि वास्तव में यदि देखा जाये तो माओवादी नक्सलवाद की सबसे बड़ी देन यही है कि यह लोगों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करके उनके निराकरण में होने वाली गड़बड़ियों के प्रति समाज को सजग करते है लेकिन उनके इस कार्य से संविधान के तहत लोगों का सुधार का दावा भी खड़े हुये हैं। समय–समय पर संबंध में सुधार करने का अपना प्रयास भी किया है। अगर नकक्सलवादियों के शक्ति स्त्रोत के वास्तविक पहलुओं पर गौर किया जाये तो निश्चय ही ये वर्तमान में सामाजिक दुर्दशा के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। आज के हालत में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवक चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको मन माफिक और उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव उन्हें काम या रोजगार भी नहीं दिला पा रहे है। आज के ही नहीं सदियों के डराये, धमकाये, दबाये गये इस वर्ग लोग जिनके पास वर्षों से सामाजिक व्यवस्था प्रशासनिक उपेक्षा तथा अपमान के खिलाफ विरोध प्रकट करने का कोई मंच नहीं था, आज नक्सलवाद के रूप में इन वर्गों के लोगों ने खोज निकाला है।

अंत सन1972 में इस आन्दोलन के सबसे बड़े नेता चारूमजूदार को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल में था तभी दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में आन्दोलन के दूसरे नेताओं कानून सान्याल, सोरन बोस, चौधरी तेजश्वराय नाम भूषण पटनायक, भुवन पटनायक ने जेल से पत्र भेजकर जेल से बाहर के नक्सलवादी नेताओं से अपील की कि वे अब तक के नक्सलवादी आन्दोलन की समीक्षा करके

उसकी त्रुटियों को दूर करें तथा आन्दोलन को नए सिरे से आगे बढ़ाएं । 1975 में जब देश में आपात स्थित लागू की तोदेश में नक्सलवादी नेताओं ने निर्णय लिया कि वह एक संयुक्त मोर्चा गठित करके सशस्त्र भूमि क्रांति के लिए नए सिरे से संघर्ष शुरू करेंगे, लेकिन उस समय भारत सरकार के जिन राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लागू किया था, उसमें नक्सलवादियों के दस विभिन्न गुट भी थे। इस संबंध के तहत दर्जनों नक्सलवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

राज्य में इस आन्दोलन की जड़े पश्चिम बंगाल में जन्में नक्सलवाद के साथ ही गहरी हुई थीं और अब काफी मजबूत हो गई हैं। करीमनगर का बंगारा गांव तो नक्सलवादियों का विश्वविख्यात अड्डा बना रहा। यहां गांव पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव का पैतृक स्थान है। नक्सलवादियों का साहस देखिए कि उन्होंने अपने एक ही आदेश से पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार में गरीबों से ली जाने वाली बेगार चुट की बजाते बंद करा दी। आंध्रप्रदेश में गरीब लोगों को जमींदारों के घर में जबरन बेगार करनी पड़ती थी। जमीदारों की हजामत भी नाई मुक्त बनाते थे। इस दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुये नक्सलवादी संगठन "पीपुल्स वार ग्रुप" तथा चन्द्रपल्ला रेड्डी ग्रुप ने दलित–पीड़ित जनता को संगठित और जागीरदारों के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। कितने ही भूस्वामियों का अपहरण किया। कितने ही धनपतियों की र्क्तापूर्वक हत्याएं की गई। पुलिस थानों पर सशस्त्र हमले हुए।

साहित्य पुनरवलोकन

(अनिल, द.क.)" नक्सलवाद और उसकी चुनौतियाँ" का अध्ययन किया और पाया कि भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं।

(Prakash, n.d.) ने भारत में नक्सलवाद का अध्ययन किया और पाया कि नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई है जहाँ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 मे सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरुप कृषितंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में ष्नक्सलवादियोंष ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पर स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। 1971 के आंतरिक विद्रोह (जिसके अगुआ सत्यनारायण सिंह थे) और मजूमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया।

(कुमारप्रमोद, 2016)में नक्सलवाद समस्या एव समाधान का अध्ययन किया और पाया कि लाल गलियारेश के रूप में जाने जाते हैं। इसमें राज्य है – पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है, जो वर्तमान सत्ता को उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड उखाड़ फेंकना चाहता है। इसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद आदि प्रमुख हैं। की वर्ग–संघर्ष की अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी शक्ति संघर्ष से पूंजीपतियों, जमीदारों, साहुकारों और शासकों को अपना 25 मई 2013 दरभा घाटी के हमले के बाद गृहमंत्रालय भी इस नतीजे पर पहुंचा था शिकार बनाते हैं। अतः इनकी मुख्य धारणा सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना करना है। कि वाम–चरमपंथियों की लोकप्रियता व दबाव दोनों बढ़ रहे हैं। अब इनके लोग व विचार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आ गए हैं, कुछ प्रतिष्ठित शैक्षणिक नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारिक एक हिंसक आन्दोलन है। नक्सलवादी संस्थानों में इनका प्रभाव बढ़ा है। साम्यवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य एवं अधिकार मानते हैं। नक्सलवादियों के इस अधिकार को प्राप्त करने में जो बाधा पहुंचाते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहिए, तभी नक्सलवादियों के कार्यक्रम रू– सर्वहारा तंत्र की स्थापना हो सकेगी, ऐसी उनकी धारणा है। उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। लेकिन अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिए एक सरकारी सम्पत्ति लूटना या नष्ट करना। बड़ी चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक सुरक्षा के रूप में उभरा है। पुलिस बलों पर लगातार हमले कर जनता का सरकार पर से विश्वास डिगाने सरकारें अभी तक नक्सल समस्या की प्रकृति भी निर्धारित नहीं कर पा रही हैं। सरकारों के सामने नक्सलवाद को लेकर हमेशा यह दुविधा रही है कि इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना जाए अथवा एक सामाजिक–आर्थिक या राजनीतिक समस्या। जन अदालतों का संचालन करना एवं बर्बरता से त्वरित न्याय करना। सरकार नक्सलवादियों के प्रति दमन की रणनीति अपना रही है।

(Sunita, 2018)में नक्सलवाद एक अध्ययन का अध्ययन किया और पाया कि नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या हैं और बीते हुए कुछ सालों में इसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में नक्सलियों का प्रभाव पशुपति (नेपाल) से तिरूपति (आंध्रप्रदेश) तक हो चुका है। धन बल में ये काफी मजबूत हैं। नक्सली क्षेत्रों में आंबटित पैसा नेता अफसरों और ठेकेदारों के बीच बंट जाता है। बात यही खत्म नहीं होती और यही पैसा अंतत नक्सलियों तक पहुंच ही जाता है जिसका उपयोग वे हिंसात्मक गतिविधियों में करते हैं। देश के लगभग 40 प्रतिशत भू – भाग पर उनकी समानांतर सरकार चलती है। देशभर में इनकी संख्या 1 लाख से 2 लाख तक मानी जाती है। नक्सलवादी समस्या आज किसी अकेले राज्य की समस्या नहीं बल्कि यह कई राज्यों की साझा समस्या है। जिसमें छतीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्रप्रदेश, झारखंड आदि प्रमुख राज्य हैं जो इनकी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसे वर्तमान में एक अहम समस्या के रूप में देखा जाए और नासुर बन चुके इस रोग का नये सिरे से सभी राज्यों से बातचीत करके सामाधान निकाला जाए। नक्सली समाज के ऐसे वर्ग के लोग है जिनकी बुनियादी जरूरतें एक सीमा तक ही हैं व्यवस्था चलाने वाले अधिकारी और सरकार भ्रष्टाचार के कारण इनकी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग हथियार उठाने लग गए। इन लोगों को जन्म देने का श्रेय नेता कानून मीडिया को जाता हैं। मीडिया वालों ने नेता और कानून के इस खेल में नक्सलियों के अधिकार की लड़ाई को अपराध की प्रवृत्ति बताकर हमेशा पैसों वालों का ही साथ दिया और इन आम लोगों को समाज और देश के दुश्मन बताकर नक्सलवादी नाम दे दिया। सामाजिक आर्थिक कारण भी नक्सलवादी को पनपने में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। किसी भी समाज या व्यक्ति पर दो तरह से ही अधिकार किया जा सकता है एक शारीरिक व दूसरा मानसिक। शारीरिक रूप से अधिकार बंदूक और भय से तथा मानसिक रूप से अधिकार करने के लिए नैतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि वर्तमान शासन तंत्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हैं। इसलिए हमें सहयोग दो। नक्सलवादियों की यही रणनीति रही हैं कि आदिवासी लोगों को सामाजिक तनाव देकर उन पर अपनी मानसिकता थोपी जाए जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हें। एक और कारण आदिवासियों की अज्ञानता और अशिक्षा हैं। जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। ये अपने रास्ते से भटक कर नक्सलियों का साथ देते हैं और फिर खुद भी इस चक्कर में फंस जाते हैं।

निष्कर्ष

नक्सलवाद, एक भयानक सुरक्षा चुनौती के रुप में सामने आया है। इसका बढता प्रभाव राष्ट्र के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। नक्सलवाद की जबरदस्त सफलता का कारण आम जनता का सहयोग है। वर्तमान समय में यह गुरिल्ला कार्यवाही के तीसरे और अन्तिम चरण में हैं इस चरण में गुरिल्ला बड़े आक्रमण करता है, वही ये कर रहे है। इसलिए नक्सवादियों को आम जनता द्वारा दिए जा रहे सहयोग को समाप्त करना होगा जनता जब विद्रोही तब बनती है जब उनका विकास नही होता । इसलिए पिछडेपन व नक्सलवाद से ग्रस्ति क्षेत्रों में विकास की लहर दौडानी होगी। राजनैतिक दलों की नक्सली हमलों पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की बजाए मिल–जुल कर रणनीति बनाने की जरुरत है केन्द्र और राज्यों सरकारों का भी आपसी तालमेल की साझि इस

भयानक समस्या के निवारण हेतु प्रयास करना चाहिए। ताकि भारत जैसी उभरती शक्ति अपने आन्तरिक मामलों में उलझ कर पिछडेपन की ओर अग्रसर न हो जाए

सन्दर्भ सूची

डा० नर्वदेश्वर शुक्ल, तूणीर, वर्ष 12 अंक 1718, 15 अगस्त 2015 पृ०सं० 39

डा० सजय कुमार पृ०सं० 45, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतिया, वर्ष 2014

डा० संजय कुमार, वर्ष 2010, पृ०सं? 151 भारत की आन्तरिक सुरक्षा मुद्दे और चुनौतियां

डा०सुरेन्द्र कुमार मिश्र, तुणीर 15 अगस्त 2015,पृ०सं० 22 समसामयिक घटना चक्र, दिसम्बर 2009

डा० विनोद मोहन मिश्रा एंव डा० अभय कुमार श्रीवास्तव, तूणीर 5 अगस्त 2006. पृ०सं० 64

डा० भारती चौहान, तूणीर, 26 जनवरी 2010,पृ०सं० 58–59 दैनिक जागरण, 18 मई 2010

डा० संजय कुमार, भारत की आन्तरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, वर्ष 2011, पृ०सं०

डा० संजय कुमार, भारत की आन्तरिक सुरक्षा चुनौतियाँ वर्ष 2011, पृ० सं० 54–55

पाण्डेय, डॉ श्रीमती साधना, ”नक्सली आन्दोलन – ऐतिहासिक व वर्तमान परिदृष्टश । रवनतंदंस व िपं वित क्मउवबतंतल ंदक कमअमसवचउमदज दृ टवस. ग. 2010, पृष्ठ 250

खन्ना, सनन्तोष ष्भारत में नक्सलवदः एक विहंगम दृष्टिश महिला विधि भारती, विधि भारती परिषद् प्रकाशन, अंक – 55, नई दिल्ली, पृष्ठ 157

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एंव संवैधानिक विकासश उदृत – प्रतियोगिता दर्पण, सीरीज – 12 पेज पृष्ठ —– 76

दुबे, अभय कुमार, क्रांति का आत्म–संघर्ष श्प्रकाशन – विनय प्रकाशन 171 बी आश्रमबाग, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ —– 19–20

दासगुप्ता, विप्लव, ”नकसल आन्दोलनश प्रकाशन– मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 140—–142 द्य